भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–20 अगस्त, 2019

अनुच्छेद–370 को समाप्त करने की भारत सरकार के गैर–संवैधानिक व फासीवादी कदम के खिलाफ एवं कश्मीरी जनता की आजादी की लड़ाई के समर्थन में आगे आओ! आवाज बुलंद करो!

केंद्र में दोबारा सत्तारूढ़ हुई ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा की केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को न सिर्फ भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रस्तावों का खुला उल्लंघन करते हुए कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद–370 एवं 35–ए को समाप्त करने के फासीवादी कदम का ऐलान किया. उसके तुरंत बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश एवं जम्मु–कश्मीर को विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करते हुए जम्मु–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराया गया एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उसे कानून में बदल दिया गया. घाटी के अलगांववादी व भारत समर्थित तमाम नेताओं को जेलों में बंद या नजरबंद करके, समूची घाटी में धारा–144 व कर्फ्यू लगाकर, मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं को बंद करके, बाहरी दुनिया से हर तरह का संपर्क काटकर, कश्मीरियों के तमाम जनवादी अधिकारों को कुचलते हुए यह प्रक्रिया पूरी की गयी. पहले से ही घाटी में मौजूद 5 लाख अर्ध सैनिक व सैन्य बलों के अतिरिक्त 70 हजार फोर्स को घाटी में तैनात करके कश्मिीरियों को अपनी प्रतिक्रिया या विरोध व्यक्त करने के तमाम रास्तें बंद कर दिए गए हैं. उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है. तमाम शाला–महाविद्यालयों, छात्रावासों, मीडिया प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है. पिछले 15 दिनों से यह सिलसिला जारी है हालांकि कश्मीरी लोग उपरोक्त तमाम पाबंदियों व पैलेट गनों को धता बताते हुए, नमाज अदा करने मस्जिदों में जाते वक्त एवं अचानक गलियों में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस की फायरिंग में सैकड़ों की संख्या में घायल हो रहे हैं.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी भारत के शोषक–शासक वर्गों द्वारा कश्मीरी जनता की आजादी की आकांक्षाओं को कुचलने एवं उनके अस्तित्व, अस्मिता व आत्मसम्मान को खत्म करने के तहत अनुच्छेद–370 एवं 35–ए को समाप्त करने की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती है. हमारी पार्टी यह ऐलान करती है कि वह कश्मीरियों के अलग होने सहित आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करती है. कश्मीरियों की आजादी की लड़ाई में हमारी पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जन कमेटियां–जनताना सरकारें, जन संगठन एवं क्रांतिकारी जनता उनके साथ है.

दरअसल राष्ट्रीयता बहुल वाले एवं धार्मिक बहुल भारत को 'हिंदू राष्ट्र' में तब्दील करने के आरएसएस के घाषित एजेंडे पर अमल की शुरुआत के तौर पर कश्मीर को पहला निशाना बनाया गया है. अनुच्छेद–370 को समाप्त कर विशेष राज्य के दर्जे से घटाकर कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया है. कश्मीर के विकास के नाम पर 35–ए को खत्म करके एवं लद्दाख को कश्मीर से अलग करके मोदी सरकार ने गैर–कश्मीरियों, गैर–मुसलमानों को घाटी में बसाने, कश्मीरियों को उनकी ही धरती पर अल्पसंख्यक बनाने, उनकी जमीनों से उन्हें बेदखल करने व कश्मीर की सार्वजनिक संपदाओं व संसाधनों को देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश पर एक साथ अमल कर रही है. प्लेबिसाइट–जनमत संग्रह के जरिए अपने भविष्य का फैसला करने के कश्मीरियों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों, आखिर कश्मीर सहित तमाम विवादास्पद मुद्दों

को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करने पर सहमत शिमला समझौते को रद्दी की ठोकरी में डालते हुए भारत सरकार ने कश्मीर पर अपना एकतरफा कब्जा जताया जिसके खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद करने की जरूरत है. कश्मीर के मसले को कश्मीरियों का समझकर यदि हम उदासीन रहेंगे, तो हिंदुत्व फासीवादियों के कल के हमलों का निशाना होंगे, पूर्वोत्तर राष्ट्रीयताएं, सभी धार्मिक अल्पसंख्यक,सभी उत्पीड़ित वर्गों, तबकों, दलित, आदिवासी.

हिंदुत्व फासीवादियों का अगला निशाना हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आंदोलन ही है. साथ ही पूर्वोत्तर राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों को खत्म करना. वर्ग युद्ध/जन युद्ध के जरिए सामंती व देशी, विदेशी कॉरपोरेट लूट को खत्म करके नव जनवादी राज्यसत्ता की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ते हुए पंचायत, एरिया व डिविजन स्तर की क्रांतिकारी जन कमेटियों की सत्ता पर अमल करने वाले दंडकारण्य एवं बिहार–झारखंड सहित देश भर के आंदोलन के सफाए के लए मई, 2017 से जारी प्रतिक्रांतिकारी दमन योजना 'समाधान' के चौतरफा हमलों को और तेज करने के तहत ही आगामी 26 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह हमारे आंदोलन के इलाकों के पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं. इस हमले का माकूल जवाब देने तैयार रहना होगा.

अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को ही मोदी ने 'नया भारत' का नाम देकर 2022 तक उसे हासिल करने का लक्ष्य घोषित कर रखा है. मोदी की कल्पना का नया भारत दरअसल देश में मौजूद विभिन्न राष्ट्रीयताओं को कुचलने वाला अंधराष्ट्रवादी, हिंदू धर्मोन्मादी, उच्च जातीय प्रभुत्व व दलित उत्पीड़न वाला एवं देशभक्ति के नाम पर देश की सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों को कौड़ियों के भाव देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने वाला देशद्रोही होगा.

मोदी के पहले पांच साल के शासनकाल में यह साफ हो गया था कि हिंदुत्व फासीवादियों के हमलों के निशान हैं – मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़े व महिलाएं और इनकी वकालत करते हुए सरकारों से सवाल करने वाले जनवादी, प्रगतिशील व क्रांतिकारी बुद्धिजीवी. इनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं जैसे खान–पान, रीति–रिवाज, रहन–सहन, देवी–देवताओं को बदलने, नियंत्रित व खत्म करने लगातार सुनियोजित हमलें किए जा रहे हैं.

हमारी पार्टी दंडकारण्य सहित पूरे देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, शिक्षक–कर्मचारियों, जनवादी–प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, कलाकारों, लेखकों, इतिहासकारों, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की जनता का आह्वान करती है कि वे ऐसे हालात से निपटने आग आवें, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने, अनुच्छेद–370 व 35–ए को हटाने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें. कश्मीरियों की आजादी के आंदोलन में साथ होने का ऐलान करें. जम्मु–कश्मीर पुनर्गठन कानून को वापसे लेने की मांग करें. सड़कों पर उतरकर, रैलियां, सभा, धरना, प्रदर्शन करें. मोदी के नए भारत–हिंदुत्व फासीवादी भारत की अवधारणा के खिलाफ, नव जनवादी भारत/नव जनवादी गणराज्यों के संघ जिसमें सभी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के अलग होने सहित आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी होगी, के लिए सभी मिलकर लड़ें.

विकल्प

(विकल्प)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)